

पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ०प्र०

मुख्यमंत्री एवं केन्द्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) ने मिशन कर्मयोगी की साधना श्रृंखला की उत्तर क्षेत्रीय कार्यशाला का शुभारम्भ किया

मिशन कर्मयोगी के अन्तर्गत कार्मिक क्षमता निर्माण में उ०प्र० को प्रथम पुरस्कार, राजस्थान को द्वितीय तथा जम्मू-कश्मीर को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ

मुख्यमंत्री एवं केन्द्रीय मंत्री ने उन्नति कैपेबिलिटी इण्डेक्स तथा नेशनल करिकुलम डिजाइन फ्रेमवर्क (एन०सी०डी०एफ०) का शुभारम्भ किया

मुख्यमंत्री जी के समक्ष डॉ० राम मनोहर लोहिया उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी द्वारा विभिन्न राज्य प्रशिक्षण संस्थानों और केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर

लोक सेवक की सफलता केवल फाइलों के निस्तारण तक सीमित नहीं, बुजुर्ग, युवा, महिला, अन्नदाता किसान और जरूरतमन्द नागरिक की समस्या का समयबद्ध समाधान तथा उसके चेहरे पर सन्तुष्टि आवश्यक : मुख्यमंत्री

उ०प्र० में अब तक 19.26 लाख सरकारी कार्मिक आईगॉट कर्मयोगी पोर्टल पर पंजीकृत, लगभग चार करोड़ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण, 334 से अधिक प्रशिक्षण संस्थान उन्नति पोर्टल से जुड़े

उ०प्र० में क्षमता विकास के प्रयासों को और प्रभावी बनाने के लिए डॉ० राम मनोहर लोहिया उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी (रूपाम) को आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की आवश्यकता, क्षमता विकास आयोग इस दिशा में पहल करे तो प्रदेश सरकार और रूपाम इसके लिए तैयार

विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाना होगा,

क्षमता विकास आयोग और रूपाम मिलकर प्रत्येक अधिकारी एवं कार्मिक की कार्यक्षमता और उसकी भूमिका के अनुरूप तैनाती की व्यवस्था विकसित करें
उ०प्र० ने मिशन कर्मयोगी के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया : केन्द्रीय मंत्री

उ०प्र० उन शुरुआती राज्यों में सम्मिलित, जिन्होंने राज्य स्तर की नियुक्तियों में भी रोजगार मेले की परम्परा शुरू की

लखनऊ : 23 अक्टूबर, 2026

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एवं केन्द्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) डॉ० जितेन्द्र सिंह ने आज यहां लोक भवन में भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अन्तर्गत क्षमता विकास आयोग द्वारा आयोजित मिशन कर्मयोगी की साधना श्रृंखला की उत्तर क्षेत्रीय कार्यशाला का शुभारम्भ किया।

कार्यक्रम के दौरान मिशन कर्मयोगी के अन्तर्गत कार्मिक क्षमता निर्माण में राज्यों के प्रयासों और उपलब्धियों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। राज्य ने जनवरी, 2026 में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए सात दिवसीय क्षमता विकास कार्यक्रम का अनावरण और साधना सप्ताह में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। निर्भय नेत्री, निर्भय चेतना, कौशल सेतु और कौशल सारथी जैसी पहलों के माध्यम से प्रदेश में क्षमता विकास के व्यापक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया गया।

आईगॉट कर्मयोगी पोर्टल पर विभागों और मंत्रालयों के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के लगभग 19.23 लाख उपयोगकर्ता पंजीकृत हैं, जिनमें 99 प्रतिशत से अधिक सक्रिय हैं। उन्नति (यूनिफाइड न्यू एज नेशनल ट्रेनिंग इनिशिएटिव) के अन्तर्गत प्रदेश के 350 से अधिक प्रशिक्षण संस्थानों का पंजीकरण किया गया है। यह उपलब्धि प्रदेश के अधिकारियों, प्रशिक्षण संस्थानों और मिशन के क्रियान्वयन से जुड़े सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है।

मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की ओर से यह सम्मान रुपाम के महानिदेशक श्री एम0 देवराज, निदेशक श्री संजय कुमार और अपर निदेशक एवं नोडल अधिकारी श्री सुनील कुमार चौधरी को प्रदान किया। राजस्थान को द्वितीय तथा जम्मू-कश्मीर को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ।

उत्तर प्रदेश के बेहतर प्रदर्शन करने वाले विभागों को भी सम्मानित किया गया। श्रेणी 'क' में गृह विभाग को प्रथम और बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग को द्वितीय पुरस्कार मिला। गृह विभाग ने मिशन कर्मयोगी के अन्तर्गत 01 करोड़ से अधिक कोर्स पूर्ण करने का रिकॉर्ड बनाया। श्रेणी 'ख' में उच्च शिक्षा विभाग को प्रथम तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। श्रेणी 'ग' में हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग को प्रथम तथा प्रशासनिक सुधार विभाग को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

कार्यक्रम के दौरान क्षमता विकास आयोग की प्रमुख पहलों का शुभारम्भ किया गया। मुख्यमंत्री जी एवं केन्द्रीय मंत्री ने उन्नति कैपेबिलिटी इण्डेक्स का शुभारम्भ किया। इसके माध्यम से देशभर के एक हजार से अधिक प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता का निरन्तर मूल्यांकन करने की व्यवस्था विकसित की गई है। पहले संस्थानों की गुणवत्ता का मूल्यांकन दो वर्ष में एक बार होता था, जबकि नई व्यवस्था में निरन्तर समीक्षा और सुधार पर जोर दिया गया है।

कार्यक्रम के दौरान नेशनल करिकुलम डिजाइन फ्रेमवर्क (एन0सी0डी0एफ0) की शुरुआत भी की गई। यह रूपरेखा कर्मयोगी क्वालिटी फ्रेमवर्क और कर्मयोगी कॉम्पिटेन्सी मॉडल पर आधारित है। इसका उद्देश्य प्रशिक्षण संस्थानों को अधिकारियों की भूमिकाओं, कार्यगत आवश्यकताओं और अपेक्षित दक्षताओं के अनुरूप प्रशिक्षण की योजना बनाने तथा उसे प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए एक समान कार्यप्रणाली उपलब्ध कराना है।

मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रशिक्षण संस्थानों के बीच ज्ञान, अनुभव, विशेषज्ञता और संसाधनों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए डॉ0 राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश

प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी द्वारा विभिन्न राज्य प्रशिक्षण संस्थानों और केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि लोक सेवक की सफलता केवल फाइलों के निस्तारण तक सीमित नहीं है, बल्कि इस बात में है कि उसके पास आने वाले बुजुर्ग, युवा, महिला, अन्नदाता किसान और जरूरतमन्द नागरिक की समस्या का समयबद्ध समाधान हो तथा उसके चेहरे पर सन्तुष्टि दिखाई दे। शासन की व्यवस्था को नागरिक-केन्द्रित बनाना हम सभी का दायित्व है। इसके लिए कार्मिकों की क्षमता का निरन्तर विकास, उनकी संवेदनशीलता, जवाबदेही और कार्य के प्रति सेवा भाव आवश्यक है। इस दृष्टि से मिशन कर्मयोगी केवल प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं, बल्कि लोक सेवा की कार्यसंस्कृति में परिवर्तन लाने वाला राष्ट्रीय अभियान है।

साधना श्रृंखला की उत्तर क्षेत्रीय कार्यशाला के लिए उत्तर प्रदेश का चयन प्रदेश के कार्मिकों की क्षमता विकास के प्रयासों को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। इस कार्यशाला में आठ राज्यों एवं चार केन्द्रशासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रतिनिधियों की सहभागिता से एक-दूसरे के अनुभवों को जानने, समझने तथा श्रेष्ठ कार्यपद्धतियों को अपनाने का अवसर प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केवल डिग्री प्राप्त कर लेने अथवा नियुक्ति पत्र मिल जाने से कोई व्यक्ति पूरी तरह योग्य नहीं हो जाता। उसे नई तकनीक, बदलती आवश्यकताओं और व्यावहारिक परिस्थितियों के अनुरूप निरन्तर सक्षम बनाना आवश्यक है। टालने की कार्यसंस्कृति के कारण नागरिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए अधिकारियों और कर्मचारियों को केवल नियमों के दायरे में काम करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपनी भूमिका और दायित्व को समझकर सकारात्मक परिणाम देने के लिए तैयार होना चाहिए।

क्षमता विकास से कार्मिकों को अपने कार्य की व्यापक समझ प्राप्त होती है और वे विभागीय सीमाओं से ऊपर उठकर नागरिकों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अयोग्य व लापरवाह व्यक्ति का किसी पद पर बने रहना व्यवस्था के लिए नुकसानदेह है। ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी, जिसमें योग्य व्यक्ति को योग्य पद पर तैनात किया जाए, उसकी क्षमता का निरन्तर विकास हो तथा उसके कार्य और पदोन्नति के बीच उचित सम्बन्ध स्थापित हो।

उत्तर प्रदेश में अब तक 19.26 लाख सरकारी कार्मिक आईगॉट कर्मयोगी पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। लगभग चार करोड़ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण किए जा चुके हैं। प्रदेश के 334 से अधिक प्रशिक्षण संस्थान उन्नति पोर्टल से जुड़ चुके हैं। प्रशिक्षण की सफलता केवल पंजीकरण, पाठ्यक्रमों अथवा प्रमाणपत्रों की संख्या से नहीं मापी जानी चाहिए। इसका वास्तविक परिणाम प्रशिक्षण के बाद लिए गए बेहतर निर्णयों, सरल हुई प्रक्रियाओं, प्रभावी कार्यप्रणाली और नागरिकों को मिलने वाली बेहतर सेवाओं में दिखाई देना चाहिए। किसी पीड़ित की सन्तुष्टि और शिकायतकर्ता की समस्या का समाधान शासन की सफलता का

महत्वपूर्ण मानक है। आदतन शिकायत करने वालों के मामले अलग हो सकते हैं, लेकिन सामान्य नागरिक की समस्या का समाधान समयबद्ध तरीके से होना चाहिए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल तकनीक तेजी से शासन के स्वरूप को बदल रही हैं। लोक सेवकों को इन परिवर्तनों के अनुरूप सक्षम बनाना होगा। इसी उद्देश्य से लखनऊ स्थित डॉ० राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी को आधुनिक तकनीक और क्षमता विकास के क्षेत्र में विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तकनीक शासन को गति दे सकती है, प्रक्रियाओं को सरल बना सकती है और निर्णयों को बेहतर बना सकती है, लेकिन शासन को संवेदनशील केवल कार्मिक का सेवा भाव ही बनाता है। इसलिए तकनीकी दक्षता के साथ मानवीय संवेदना और नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व को समान महत्व देना होगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विकसित भारत का निर्माण केवल बेहतर नीतियां बनाने से नहीं होगा, बल्कि उन नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने वाले सक्षम, संवेदनशील और परिणामोन्मुखी प्रशासन की भी आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति से बाहर निकलकर विभिन्न क्षेत्रों में 36 सेक्टरल पॉलिसीज बनाई गई हैं। प्रदेश की परिवर्तन यात्रा में क्षमता विकास, बेहतर प्रशासनिक कार्यसंस्कृति और नागरिक-केन्द्रित दृष्टिकोण की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

मुख्यमंत्री जी ने इस अवसर पर तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में क्षमता विकास के प्रयासों को और प्रभावी बनाने के लिए डॉ० राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी (रूपाम) को आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है। क्षमता विकास आयोग इस दिशा में पहल करे तो प्रदेश सरकार और रूपाम इसके लिए तैयार हैं।

ग्राम पंचायतों तथा नगरीय निकायों के कार्मिकों की क्षमता विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम सहित सभी नगरीय निकायों में कार्यरत कार्मिकों को भी सक्षम बनाने की आवश्यकता है। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाना होगा। ये शासन की बुनियादी इकाइयां हैं। इनकी क्षमता को मजबूत करने के साथ जवाबदेही तय करना और इन्हें नागरिक-केन्द्रित बनाना भी आवश्यक है।

मुख्यमंत्री जी ने 'द राइट ऑफिशियल फॉर द राइट रोल' अर्थात् सही पद के लिए सही अधिकारी की अवधारणा को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर देते हुए कहा कि क्षमता विकास आयोग और रूपाम मिलकर प्रत्येक अधिकारी एवं कार्मिक की कार्यक्षमता और उसकी भूमिका के अनुरूप तैनाती की व्यवस्था विकसित करें। सम्बन्धित अधिकारी की सफलता की कहानियों, कार्य निष्पादन तथा वार्षिक गोपनीय आख्या (ए०सी०आर०) को उसकी पदोन्नति से जोड़ने की दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए। इससे योग्य व्यक्ति को उपयुक्त स्थान पर तैनात करने और प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि साधना श्रृंखला की यह कार्यशाला उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के अधिकारियों को एक-दूसरे के अच्छे अनुभवों से सीखने का अवसर प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश में किए गए अच्छे प्रयास दूसरे राज्यों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, वहीं अन्य राज्यों के अनुभवों से प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

उत्तर प्रदेश भारत की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य होने के साथ ही प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा से सम्पन्न प्रदेश है। यहां अत्यन्त उर्वर भूमि, प्रचुर जल संसाधन और देश की सबसे बड़ी युवा कार्यशक्ति उपलब्ध है। इसके बावजूद लम्बे समय तक प्रदेश अपनी सम्भावनाओं को उपलब्धियों में परिवर्तित नहीं कर पाया। इसके पीछे आवश्यक क्षमता विकास और उसे नेतृत्व प्रदान करने वाली राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव प्रमुख कारणों में से एक था। यही स्थिति प्रदेश में अव्यवस्था और अराजकता के लिए भी जिम्मेदार रही। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने इस स्थिति को बदला है। आज प्रदेश के नागरिकों और प्रशासनिक मशीनरी के सामने पहचान का संकट नहीं है, बल्कि प्रदेश अपनी उपलब्धियों के आधार पर देश में नई पहचान स्थापित कर रहा है।

विगत साढ़े नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश की स्टेट जी0डी0पी0, बजट और प्रति व्यक्ति आय को तीन गुना बढ़ाने में सफलता प्राप्त हुई है। वर्ष 2017 में प्रदेश के पास मात्र डेढ़ एक्सप्रेस-वे थे, जबकि आज देश के एक्सप्रेस-वे नेटवर्क का लगभग 60 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है। प्रदेश के पास देश का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क, सबसे बड़ा रेल नेटवर्क और एयर कनेक्टिविटी का व्यापक नेटवर्क है। वर्ष 2017 में प्रदेश में केवल दो अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे क्रियाशील थे, जबकि आज पांच अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और 17 घरेलू हवाई अड्डे सफलतापूर्वक संचालित हैं। देश की पहली रैपिड रेल उत्तर प्रदेश में संचालित हो रही है। प्रदेश के सात शहरों में मेट्रो के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। इन उपलब्धियों से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश ने प्रत्येक क्षेत्र में विकास के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले आम नागरिक का विश्वास शासन-प्रशासन की व्यवस्था से उठ चुका था। व्यवस्था नागरिक-केन्द्रित होने के बजाय सत्ता-केन्द्रित हो गई थी। युवाओं को सरकारी नौकरी का विज्ञापन निकलते ही चयन प्रक्रिया में सिफारिश, लेनदेन और भ्रष्टाचार की आशंका सताने लगती थी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता का अभाव था, प्रत्येक घर में शौचालय उपलब्ध नहीं थे और बड़ी संख्या में लोग छतविहीन मकानों में रहने के लिए मजबूर थे। गरीबों के सामने भोजन की समस्या थी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज प्रदेश में 65 लाख गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराने में सफलता मिली है। तीन करोड़ से अधिक परिवारों के घरों में शौचालय बनाए गए हैं। 15 करोड़ से अधिक लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। विगत साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश में भूख से किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। सरकार की योजनाओं का लाभ ईमानदारी के साथ पात्र गरीबों तक पहुंचा है।

बुन्देलखण्ड और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में पहले रेल एवं टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाना पड़ता था, जबकि आज हर घर नल योजना के माध्यम से लोगों तक पानी पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। पहले चार-पांच जनपदों में ही बिजली की समुचित उपलब्धता थी, जबकि आज सभी 75 जनपदों में नागरिकों को समान रूप से विद्युत उपलब्ध हो रही है। कृषि विकास की दर को आठ प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत तक पहुंचाने में सफलता मिली है। पहले चीनी मिलें औने-पौने दाम पर बिक रही थीं, जबकि आज गन्ना किसानों को उनके गन्ना मूल्य का भुगतान नियमित रूप से हो रहा है। ये परिवर्तन प्रदेश में शासन की प्राथमिकताओं और कार्यप्रणाली में आए बदलाव का परिणाम हैं।

मुख्यमंत्री जी ने क्षमता विकास के महत्व को स्पष्ट करते हुए इन्सेपलाइटिस नियन्त्रण का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में वर्ष 2017 से पहले इन्सेपलाइटिस की बीमारी के कारण बड़ी संख्या में बच्चे प्रभावित होते थे और उनकी मृत्यु होती थी। मध्य जुलाई से मध्य नवम्बर तक इस बीमारी का प्रकोप रहता था। इसे केवल स्वास्थ्य विभाग की समस्या मान लिया गया था, जबकि इसके समाधान के लिए अनेक विभागों के समन्वित प्रयास आवश्यक थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 में प्रदेश की जिम्मेदारी सम्भालने के बाद उन्होंने इन्सेपलाइटिस को केवल स्वास्थ्य की समस्या मानने के बजाय स्वच्छता, शुद्ध पेयजल और जन-जागरूकता से जुड़ी व्यापक चुनौती के रूप में देखा। प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता सम्बन्धी अभियान को आगे बढ़ाते हुए नगर विकास, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा, दिव्यांगजन कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास विभाग को भी इस अभियान से जोड़ा गया। सभी विभागों को समन्वित रूप से कार्य करने का दायित्व दिया गया। जिस बीमारी के कारण 40 वर्षों में 50 हजार बच्चों की मृत्यु हुई थी, उसे उत्तर प्रदेश ने पूरी तरह नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की। आज प्रदेश में इन्सेपलाइटिस से होने वाली मौतें शून्य हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस अभियान की सफलता के पीछे क्षमता विकास की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित फील्ड में कार्यरत कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया। एक से 15 वर्ष तक के बच्चों को प्रभावित करने वाली इस बीमारी के संबंध में पैरामेडिकल स्टाफ, बाल रोग विशेषज्ञों, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों की भूमिकाएं निर्धारित की गईं। 108 एम्बुलेन्स सेवा को प्रभावी बनाने के साथ ही मार्च से जून तक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए। जुलाई से ग्राम पंचायत स्तर से मेडिकल कॉलेज तक सभी विभागों के समन्वय और मुख्यमंत्री कार्यालय से निगरानी की व्यवस्था की गई। इसके परिणामस्वरूप लगभग 40 वर्षों से चली आ रही समस्या का समाधान करने में मात्र दो वर्ष लगे। यह उदाहरण बताता है कि उचित प्रशिक्षण, समन्वय, जवाबदेही और प्रभावी निगरानी से कठिन समस्याओं का समाधान भी सम्भव है।

केन्द्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ० जितेन्द्र सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने मिशन कर्मयोगी के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। राजस्थान और जम्मू-कश्मीर ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। रैंकिंग में आगे आने वाला राज्य दूसरे राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। यह प्रतिस्पर्धा सभी राज्यों को अपनी कार्यप्रणाली बेहतर बनाने और क्षमता विकास को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से प्रशासनिक सुधारों को नई दिशा मिली। सरकार गठन के बाद राजपत्रित अधिकारियों से दस्तावेजों का सत्यापन कराने की पुरानी व्यवस्था समाप्त की गई। इससे देश के युवाओं पर विश्वास जताने और उन्हें अनावश्यक औपचारिकताओं से मुक्त करने का संदेश गया। प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2014 में लाल किले से अपने संबोधन में सरकारी नियुक्तियों में साक्षात्कार की व्यवस्था समाप्त करने का आह्वान किया था, ताकि पक्षपात और भेदभाव की शिकायतों को दूर किया जा सके। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डी०ओ०पी०टी०) ने तीन महीने के भीतर इस प्रक्रिया को पूरा किया और पहली जनवरी से सम्बन्धित व्यवस्था लागू कर दी गई।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि रोजगार मेले के माध्यम से सरकारी नियुक्तियों को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया गया है। अब तक 20 रोजगार मेले आयोजित किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश उन शुरुआती राज्यों में सम्मिलित है, जिन्होंने राज्य स्तर की नियुक्तियों में भी रोजगार मेले की परम्परा शुरू की।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में पूरे देश में एक वर्ष में लगभग दो लाख शिकायतें दर्ज होती थीं। आज यह संख्या बढ़कर लगभग 25 लाख हो गई है। शिकायतों के निस्तारण की दर लगभग 95 से 97 प्रतिशत तक पहुंचने से नागरिकों में यह विश्वास बढ़ा है कि उनकी शिकायत का उत्तर मिलेगा और उसका समाधान होगा। पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की व्यवस्था शुरू की गई, जिसका अनुसरण उत्तर प्रदेश ने भी किया। पहले बुजुर्गों को प्रतिवर्ष जीवित होने का प्रमाण देने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बायोमेट्रिक और फेस रिकग्निशन तकनीक के उपयोग से इस प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि क्षमता विकास आयोग की अवधारणा प्रधानमंत्री जी की सोच का परिणाम है। इसका उद्देश्य सरकारी कार्मिकों को केवल नियमों और फाइलों तक सीमित रखने के बजाय उनकी भूमिका के अनुरूप सक्षम बनाना है। अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारी सकारात्मक ढंग से निभाने के लिए तैयार करना ही क्षमता विकास का मूल उद्देश्य है।

प्रशिक्षण संस्थानों को उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में विकसित करने और उनके बीच समन्वय स्थापित करने के लिए संरचित ढांचा आवश्यक है। इसी उद्देश्य से साधना सप्ताह का आयोजन अप्रैल 2025 में किया गया था, जिसमें परम्परा, तकनीक और ठोस परिणामों पर विशेष जोर दिया गया। परम्परा और आधुनिक तकनीक के समन्वय से ही विकास को सार्थक

बनाया जा सकता है। आईगॉट कर्मयोगी पोर्टल पर देशभर के लगभग 1.70 करोड़ अधिकारी एवं कार्मिक पंजीकृत हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के 19 लाख से अधिक कार्मिक इस पोर्टल से जुड़े हैं। योग और आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों में उल्लेखनीय सहभागिता रही है। योग परम्परा का प्रतीक है, जबकि ए0आई0 आधुनिक तकनीक का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर प्रदेश ने इन दोनों क्षेत्रों में प्रशिक्षण के माध्यम से परम्परा और तकनीक के समन्वय का उदाहरण प्रस्तुत किया है।

केन्द्रीय मंत्री ने उन्नति पहल का उल्लेख करते हुए कहा कि यह प्रशिक्षण संस्थानों को एक साझा मंच पर लाने की महत्वपूर्ण व्यवस्था है। देशभर में प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमताओं का उपयोग, विशेषज्ञता का आदान-प्रदान और संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने से प्रशिक्षण व्यवस्था मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश के 350 से अधिक प्रशिक्षण संस्थानों के पंजीकरण की उपलब्धि उल्लेखनीय है। प्रशिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग और श्रेष्ठ कार्यपद्धतियों के प्रसार से उत्तर प्रदेश के अनुभव दूसरे राज्यों तक पहुंच सकेंगे। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सुशासन के क्षेत्र में एक मॉडल के रूप में आगे बढ़ता रहेगा।

कार्यशाला में क्षमता विकास आयोग की अध्यक्ष श्रीमती एस0 राधा चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में अधिकारियों को नई पहल करने, निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने, नेतृत्व गुणों को मजबूत करने तथा तकनीक के माध्यम से नवाचार करने के लिए प्रोत्साहन मिला है। उत्तर प्रदेश के अनेक नीतिगत प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए जाने योग्य मॉडल बने हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री शशि प्रकाश गोयल ने कहा कि शासन की योजनाओं की सफलता उनकी संख्या से नहीं, बल्कि इस बात से निर्धारित होती है कि उनका लाभ आम नागरिकों तक संवेदनशीलता, प्रभावशीलता और समयबद्धता के साथ पहुंच रहा है या नहीं। नागरिकों की समस्याओं का निराकरण ही प्रशासन का मूल उद्देश्य है। क्षमता विकास आयोग सरकारी कार्मिकों की दक्षता और नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

कार्यक्रम के दौरान उन्नति पोर्टल की उपयोगिता पर आधारित एक लघु फिल्म प्रदर्शित की गई।

इस अवसर पर पर क्षमता विकास आयोग की सदस्य डॉ0 अलका मित्तल, सचिव श्री जगदीप गुप्ता, रुपाम के महानिदेशक श्री एम0 देवराज सहित विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी, प्रशिक्षण संस्थानों के महानिदेशक एवं निदेशक, विषय विशेषज्ञ, तकनीकी विशेषज्ञ, कर्मयोगी कर्तव्य कार्यक्रम के मास्टर ट्रेनर्स तथा उत्तर प्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।